छत्तीसगढ़ की प्रथम विधान सभा
द्वितीय सत्र

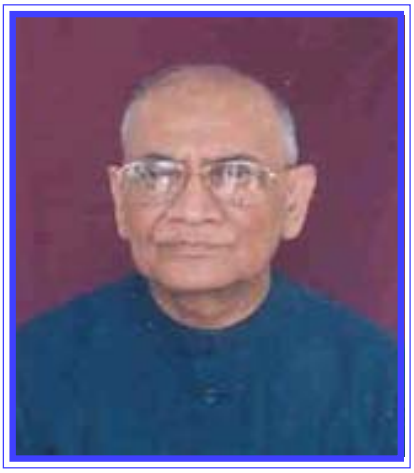

श्री दिनेश नंदन सहाय

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 27 फरवरी, 2001

माननीय सदस्यगण,

नए वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के पहले सत्र के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस नवजात राज्य की जनता की परिपक्वता का जिक्र दो महत्वपूर्ण प्रसंगों के माध्यम से करना चाहता हूं। पहला मौका था गुजरात के विनाशकारी भूंकप का। अपने राज्य के भीषण सूखे के बावजूद छत्तीसगढ़ की जनता जिस तरह भूकंप पीड़ितों की पीड़ा में सहभागी बनी, पीड़ितों की मदद करने के लिए लोग जिस तरह से आगे आए और दिल खोलकर सहायता की, वह वास्तव में गर्व से भर उठने का अवसर था। दूसरा अवसर राज्य में हुए शांतिपूर्ण उपचुनाव का था। लोकतांत्रिक मर्यादाओं तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन का यह सफल आयोजन था। इसके लिए मैं निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं तथा समस्त नागरिकों को बधाई देता हूं।

2. आपको स्मरण होगा कि पिछले सत्र में मैंने राज्य के गठन से जनता के दिलों में जागी नई उम्मीदों का जिक्र किया था। नए राज्य की विधानसभा के प्रथम अधिवेशन को अभी सिर्फ ढाई माह ही बीते हैं। इस बीच सरकार को काम करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिला, लेकिन हर्ष का विषय है कि फिर भी इस छोटी अवधि में जनाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं।

3. माननीय सदस्यगण, भीषण सूखे की प्राकृतिक विपदा आने वाले कुछ महीनों में और अधिक विकराल रूप लेगी। ऐसे हालातों में किसानों, खेतिहर मजदूरों और गरीबों की पीड़ा को हम अपने अन्तर्मन की गहराई तक महसूस कर रहे हैं। पिछले सत्रावसान के बाद राज्य भर से 'आनावरी' प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश में 61 तहसीलें पूरी तरह सूखे से प्रभावित हुई हैं। इन तहसीलों में पीड़ित जनता को राहत पहुंचने के भगीरथ प्रयासों में मेरी सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। जहां पहले केवल राज्य के सीमित संसाधनों का ही उपयोग हो पा रहा था, वहीं मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से केन्द्र शासन से हमारी 470 करोड़ रू. की मांग पर लगभग एक माह पूर्व 1.6 लाख टन चावल और 20 फरवरी को केन्द्र से 40 करोड़ रूपये की नकद सहायता प्राप्त हुई है। काम के बदले अनाज योजना में 25 प्रतिशत नकद तथा 75 प्रतिशत चावल के अनुपात में इस खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा केन्द्र से अनाज के रूप में मनुष्यों के लिए अनुपयुक्त अनाज को पशुचारा के रूप में उपयोग करने के आदेश प्राप्त हुए हैं जिसका उपयोग इस खाद्यान्न के पशु आहार हेतु उपयुक्त पाए जाने के बाद किया जाएगा। वर्तमान में सूखा प्रभावित जिलों में विभागीय और राहत मद से 5,605 पंचायतों में 17,205 कार्य चल रहे हैं जिसमें 6,29,364 मजदूर कार्यरत हैं। प्राप्त सहायता का पूरा–पूरा उपयोग जरूरतमंदों के हित में, समय पर किए जाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। यह निर्णय भी लिया गया है कि न केवल प्रभावित तहसीलों की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक रोजगार मूलक कार्य, और आगे चलकर हर गांव में एक कार्य, बरसात आते तक निरंतर चलें, बल्कि अब मेरी सरकार ने शेष तहसीलों के सूखा प्रभावित ग्रामों में भी राहत कार्य खोलने के निर्देश

जारी कर दिये हैं। इन निर्णयों पर कारगर अमल की व्यवस्था भी की गई है तथा राज्य की प्रभावित जनता को समय पर आवश्यकतानुसार राहत पहुंचाने में कोताही कतई बर्दाश्त न किए जाने का स्पष्ट संदेश भी शासन और प्रशासन के हर स्तर पर दिया जा चुका है। हर पंचायत में एक क्विंटल अनाज रखा गया है ताकि ग्राम पंचायत जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार तत्काल उपलब्ध करा सके।

4. राज्य बनने के बाद मेरी सरकार ने राज्य की जनता को सूखे की नियति से स्थाई निजात दिलाने के लिये पहला संकल्प जल संग्रहण और सिंचाई क्षमता में वृद्धि का लिया था। मुझे खुशी है कि इस दिशा में गंभीर प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं। प्रदेश में शासकीय स्त्रोतों से वर्तमान सिंचाई क्षमता 13.39 लाख हेक्टेयर है, जिसमें शीघ्र वृद्धि के लिये तीन बड़ी परियोजनाओं हसदेव बांगो, जोंक तथा शिवनाथ व्यपवर्तन से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। आगामी वर्ष इन्हीं योजनाओं से लगभग 36 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसके अलावा नाबार्ड से स्वीकृत योजनाओं में तेजी लाकर राज्य में सिंचाई क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की जाएगी। मार्च तक लगभग 10 हजार हेक्टेयर भूमि में इन योजनाओं से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाएगी। सिंचाई नहरों के संचालन एवं संधारण की जिम्मेदारी जनभागीदारी से पूरी की जाएगी, जिसके लिए हितग्राहियों की 946 जल उपभोक्ता संस्थाएं क्रियाशील हैं। मेरी सरकार की नजर में सिंचाई क्षमता में वृद्धि का मतलब किसानों, मजदूरों सहित पूरे राज्य की जनता की खुशहाली और राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना है।

5. शुद्ध पेयजल तथा निस्तार हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को मेरी सरकार अपना प्रमुख कर्तव्य मानती है। पेयजल के अलावा इस वर्ष ग्रामीण अंचलों में निस्तारी तालाबों के सूखने की आशंका को देखते हुए शुरू की गई 'इंदिरा गांव–गंगा योजना' में मात्र तीन माह में 1991 गांवों में सफल जल स्त्रोत विकसित किये गये हैं। 163 गांवों में कार्य प्रगति पर है। जैसा मैंने विगत सत्र में कहा था, चरणबद्ध रूप से इस योजना में सभी विद्युतीकृत गांवों में नियमित व विश्वसनीय जल–स्त्रोत बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में भू–जल के गिरते स्तर को रोकने, जल संरक्षण और पानी की बर्बादी रोकने के लिये सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने का एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

6. शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष 2000–2001 में अब तक 2,979 बसाहटों में 3,544 हैण्डपम्प लगाए जा चुके हैं। जिन ग्रामों में सफल पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे ग्रामों में परिवहन के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जाएगा। पेयजल की संभावित जटिल समस्या का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार को लगभग 99 करोड़ रूपए के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

7. राज्य का तेजी से विकास करने के लिए अच्छी सड़कों का होना अनिवार्य है। राज्य के गठन के बाद सड़कों के उन्न्यन एवं निर्माण कार्य का मास्टर प्लान बनाने की पहल की गई है। इस कार्य हेतु ख्याति प्राप्त परामर्शदाताओं को आमंत्रित कर राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप योजना बनाई जा रही है। राज्य

में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों में से 11 सड़कों के उन्नयन का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। 15 सड़कों के उन्नयन हेतु केन्द्र सरकार से सी.आर.एफ. योजना के तहत स्वीकृति प्राप्त की गई है। इन कार्यों की कुल लागत 66.64 करोड़ रू. है, जिसमें से केन्द्र से 7.68 करोड़ रू. की राशि प्राप्त हुई है। नाबार्ड की ऋण सहायता से 7.93 करोड़ रू. की लागत के 9 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष कार्य जारी हैं। सरकार द्वारा विगत 3 माह में 6 बड़े पुलों का निर्माण पूर्ण कर उन्हें आम जनता की सुविधा के लिए प्रारंभ किया जा चुका है और अन्य 37 पुलों का निर्माण कार्य जारी है।

8. रायगढ़–पत्थलगांव मार्ग के सुधार हेतु निजी पूंजी निवेश से बी.ओ.टी. के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। रायपुर में टाटीबंद चौक से भिलाई के नेहरूनगर चौक तक राष्ट्रीय राजमार्ग के चार लेन निर्माण हेतु निविदा का प्रकाशन किया जा चुका है। इसी प्रकार, रायपुर में टाटीबंद चौक से भनपुरी होते हुए बिलासपुर तक मार्ग के मजबूतीकरण हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। निजी पूंजी निवेश के अन्तर्गत दुर्ग शहर की बाई–पास सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर आम जनता के आवागमन हेतु प्रारंभ कर दिया गया है।

9. छत्तीसगढ़ के गांव–गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु मेरी सरकार ने 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यक्रम' को अमल में लाने की पुख्ता व्यवस्था की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007 तक 500 से अधिक आबादी के सभी ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 19,725 ग्रामों में से केवल 2,722 ग्राम पक्की सड़कों से जुड़े हैं तथा 17003 ग्रामों को अभी भी पक्की सड़कों से जोड़ना शेष है। इन सभी ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने के लिए 61,086 किलोमीटर की पक्की सड़क निर्माण का 4847.98 करोड़ रू. का प्रस्ताव भारत शासन को भेजा गया है। इस योजना के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में 1000 से अधिक आबादी के ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके लिए इस वर्ष 87 करोड़ रू. का प्रावधान है जिसमें से अभी तक 9.54 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

10. रायपुर में नई राजधानी के निर्माण हेतु निविदाएं बुलाकर ख्याति प्राप्त नगर निवेशकों से राजधानी की संरचना का कार्य प्रारंभ किया जाना है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार के उपक्रम सिडको, मुंबई को सलाहकार नियुक्त किया गया है जो नई राजधानी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अवधारणाएं आमंत्रित करेगा। इस बीच रायपुर की वर्तमान अधोरंचना को मजबूत बनाने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा जा रहा है। रायपुर में शासकीय कर्मचारियों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विकास प्राधिकरण और नगर निगम के 1025 मकान आधिपत्य में लिए गए हैं। इसके अलावा 970 मकान इन्हीं एजेन्सियों से आगामी 6 माह में प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रदेश के नगरीय निकाय, अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इसके लिए मेरी सरकार ने विगत नवम्बर माह से अभी तक प्रदेश के 75 नगरीय निकायों को कुल 34.02 करोड़ रू. की राशि दी गई है।

11. प्रथम अधिवेशन में मैंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के संकल्पों का जिक्र किया था। इसके अनुरूप शिक्षा को जमीनी जरूरतों, नौनिहालों के भविष्य निर्माण तथा वक्त की मांग के अनुरूप बनाने के अनेक प्रयास मेरी सरकार द्वारा किए गए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, वैश्वीकरण की गतिविधियों तथा टेक्नोलॉजी की महत्ता वाले इस युग में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई के लिए राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, रायपुर द्वारा विशेष पाठ्यक्रम एवं 23000 चिन्हित शिक्षकों को प्रशिक्षण की योजना तैयार की गयी है। यह कार्यक्रम आगामी शिक्षा सत्र से पूर्व ही चरणबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।

12. प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण से लेकर उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र तक गुणवत्ता लाने के लिए कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं। साक्षरता कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में नवसाक्षरों के लिए 'सतत् शिक्षा कार्यक्रम' आगामी वर्ष से लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा के अंतर्गत तकनीकी पाठ्यक्रमों में अधिक संख्या में छात्रों को लाभान्वित करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी शिक्षा सत्र से एम.बी.ए., एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता क्रमशः लगभग 40 से 80 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी।

13. मेरी सरकार ने बालिकाओं को शिक्षित तथा आत्मनिर्भर बनाने की जो योजना प्रारंभ की थी, वह पूरे राज्य में आकार लेने लगी है। सरकारी शालाओं में पढ़ने वाली गरीब परिवारों की बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा देने वाली 'इंदिरा सूचना शक्ति योजना' पहले चरण में 50 शालाओं में प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत कुल एक लाख छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन परिवारों से आई प्रतिभावान छात्राओं की आर्थिक सहायता के लिए स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति चिकित्सा शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति' भी प्रारंभ की गई है।

14. 'छत्तीसगढ़ में कोई भी महिला बेसहारा नहीं रहे' इस प्रतिबद्धता के साथ मेरी सरकार ने 'इंदिरा सहारा योजना' प्रारंभ की है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक की विधवा एवं परित्यक्ता निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 150 रू. सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का प्रावधान है। अब तक राज्य में 39986 महिलाओं को इस योजना का सहारा देने के लिए चिन्हित कर प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। यह राज्य में 288067 निराश्रितों को दी जा रही वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त है। वृद्ध, निःशक्त तथा अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के सभी कार्यक्रम पूर्ववत् संवेदनशीलता के साथ लागू किये जाते रहेंगे। मेरी सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक सुधार आंदोलन का सम्मान करते हुए 2 लाख रू. का ज्योतिबा फुले स्मृति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है जो नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाली संस्था अथवा व्यक्ति को प्रदान किया जायेगा।

15. मेरी सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य में नारी को मातृ शक्ति का सम्मान प्रदान करने के लिये व्यावहारिक योजनाएं बनाई जाएंगी। इस दिशा में तत्परतापूर्वक कार्य किया गया है। प्रदेश में 152 समेकित बाल विकास परियोजनाएं तथा 20,285 आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्रभावशाली ढंग से संचालित करने की पहल

की गयी है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में 12,050 स्व–सहायता समूहों का गठन किया गया है जिनमें 1,73,500 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

16. मेरी सरकार ने वन क्षेत्रों में समन्वित विकास का जो संकल्प लिया था, उस दिशा में मजबूती से कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों और उसके 5 कि.मी. की परिधि में स्थित गांवों में रहने वाले लोगों के समन्वित विकास हेतु 'वन विकास अभिकरण' का गठन किया गया है। इसके लिए 2,955 वन सुरक्षा, 3,107 ग्राम वन तथा 199 पारिस्थितिकीय विकास समितियों को समन्वित किया जा रहा है। यह योजना प्रथम चरण में बस्तर, महासमुंद, पूर्व सरगुजा वन मंडलों में लागू की जाएगी। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये पृथक वन परियोजना प्रस्तावित की गयी है। औषधीय, बहुमूल्य तथा विलुप्तप्राय पौधों के नैसर्गिक संरक्षण–संवर्धन के लिए 'वनस्पति वन योजना' प्रस्तावित की गयी है। आदिवासी एवं लोक चिकित्सकों की पहचान कर उनकी मदद से स्थानीय औषधि केन्द्र विकसित किया जाएगा।

17. वनोपजों का सीधा लाभ वनवासियों को देने के लिए और तेंदूपत्ता संग्रह करने वाले मजदूरों को मालिक बनाने के लिए, तेंदूपत्ता बेचने से प्राप्त शत–प्रतिशत लाभ संग्रहकों को ही बांटने का निर्णय लिया गया है। शाखकर्तन की दरें दोगुनी कर दी गई हैं। शाखकर्तन का सीधा संबंध तेंदूपत्ता की गुणवत्ता से होता है, इसलिए अच्छे उत्पादन का फायदा पुनः मजदूरों को होगा। इसके अलावा सही भुगतान तथा गुणवत्ता तय करने के लिए फड़ स्तर पर समिति बनाकर जनभागीदारी तय की गई है। समितियों की सदस्यता की सूक्ष्म जांच करने का निर्णय भी लिया गया है। ताकि जो वास्तविक मजदूर नहीं हैं वे समितियों पर नियंत्रण न कर सकें। तेन्दूपत्ता नीति का कार्यान्वयन अब जिला कलेक्टरों की देखरेख में जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। केन्द्र शासन तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई छूट की सीमा में वनों के विदोहन का कार्य प्रारंभ किया गया है। वनों में बांस तथा लकड़ी कटाई के अतिरिक्त वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों के जरिए रोजगार जुटाया जा रहा है। राज्य के 425 वन ग्रामों के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु 45.74 करोड़ रू. की त्रिवर्षीय योजना तैयार करके केन्द्र को भेजी जा चुकी है जिससे वन ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

18. नागरिकों की उत्तम सेहत मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। राज्य के गठन के साथ ही ग्रामीण अंचलों में मलेरिया के फैलाव की खबरें आने लगी थीं। सरकार ने युद्धस्तर पर प्रयास कर मलेरिया की रोकथाम का निर्णय लिया था। इस दिशा में व्यापक प्रयास किये गये और प्रकोप पर काबू पाया गया। आगामी वर्ष मलेरिया का प्रकोप ना हो इसके लिए विस्तृत दीर्घकालिक योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। केन्द्र से प्राप्त कुल 400 टन मच्छर निरोधक छिड़काव कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 1800 टन मच्छर मारने की दवा की मांग की गई है। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को वांछित स्तर तक लाने एवं दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को समुचित रूप से पहुंचाने के लिए नए चिकित्सा महाविद्यालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, अत्याधुनिक मानसिक आरोग्य चिकित्सालय एवं नर्सिंग कालेज खोले जाएंगे।

जिसके लिए निजी क्षेत्र को पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्नातकोत्तर संस्थान खोलना, एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष से भर्ती सीट्स की संख्या बढ़ाना एवं नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करना भी सरकार की प्राथमिकता में है। बिलासपुर में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर भारतीय चिकित्सा परिषद के निरीक्षण और अनुमोदन की प्रतीक्षा है। चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में अत्याधुनिक सुविधायुक्त डायग्नोस्टिक सेन्टर निजी भागीदारी से मुहैया कराए जाएंगे। ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए तीन वर्षीय चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो चुका है। पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आवश्यक विधेयक तैयार किया जा रहा है। विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता तथा मान्यता के लिए 'छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद' का गठन शीघ्र किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम स्तर पर जनस्वास्थ्य रक्षक, प्रशिक्षित दाई के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रशिक्षण की योजना बनाकर क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है।

19. 'छत्तीसगढ़ी' को समृद्ध करने के साथ ही उसे गौरवशाली स्थान पर भी प्रतिष्ठित करने के लिए इसे शासकीय तथा अन्य प्रयोजनों हेतु सरकारी मान्यता दिलाने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया गया है।

20. मेरी सरकार छत्तीसगढ़ की लोक–संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए उसके स्वाभाविक विकास में स्वयं कोई हस्तक्षेप करने के बजाए यथोचित वातावरण बनाने तथा व्यापक जनभागीदारी से संसाधन जुटाने की भूमिका का निर्वाह करेगी। संस्कृति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा के अभिलेखन, प्रदर्शन, प्रचार–प्रसार, प्रकाशन के साथ–साथ विभिन्न इलाकों में क्षेत्रपरक विकास को गति देने के लिए ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो स्थानीय लोगों के जीवन से जुड़ी हो। मेरी सरकार ने बहुआयामी सांस्कृतिक परिसर की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसमें कला एवं जीवन के संबंध, संस्कृति के साथ विकास एवं विभिन्न विकास योजनाओं के सांस्कृतिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रदेश के सामूहिक वाचनालयों को एक सूत्र में नेटवर्क के माध्यम से बांधा जाएगा और सार्वजनिक ग्रंथालय को विकसित किया जाएगा। सांस्कृतिक परिसर के साथ ही मुक्तांगन तथा 'क्लोजडोर' संग्रहालय को निरंतर सृजनशील संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा। होटल निर्माण अथवा पर्यटन व्यवसाय में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अलबत्ता पर्यटन से पड़ोसी राज्यों एवं देश–विदेश के लोगों को जोड़ने के लिए प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जाएगा। पर्यटन विकास के लिए निजी निवेशकों को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकार को स्व. चन्दूलाल चंद्राकर की स्मृति में 2 लाख रू. का पुरस्कार भी देने का निर्णय लिया गया है।

21. युवा शक्ति को विकास का एक प्रमुख संसाधन मानते हुए मेरी सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे विकास में हाथ बंटाते हुए युवा गौरवान्वित हों और स्वयं लाभान्वित भी हों। स्वस्थ वातावरण में वे अपने कैरियर और अवसरों का उपयोग करने के लिए सतर्क तथा शिक्षित हों। छत्तीसगढ़ राज्य के भावी विकास के बारे में युवाओं के सपने, उनकी आकांक्षाएं तथा सरकार से उनकी उम्मीदों के बारे में सीधे चर्चा

करने का अभिनव प्रयास मेरी सरकार ने किया। इसके लिए युवा आयोग द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालयों तथा महाविद्यालयों से आए प्रतिनिधि छात्र–छात्राओं ने सक्रियता से भाग लिया।

22. राज्य में खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन एवं युवा वर्ग में निहित साहसिक गुणों को बनाए रखने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य मुख्यालय पर सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम और जिला मुख्यालयों पर क्रमशः खेल परिसर बनाए जाएंगे। राजधानी रायपुर में 50 लाख रू. की लागत से 'राजीव गांधी स्पोर्ट्स हॉस्टल' का निर्माण स्टेडियम परिसर में कराया जा रहा है। ग्राम्यांचल में क्रीड़ा–आंगनों तथा आदिवासियों की नैसर्गिक खेल प्रतिभा के संरक्षण हेतु स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण भी किया जाएगा और आदिवासी क्षेत्रों में लघु तथा दीर्घावधि प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन हमारी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। इसी कड़ी में जशपुर में एस्ट्रोटर्फयुक्त हॉकी स्टेडियम का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा रहा है। प्रदेश में हर शाला के लिए खेल के मैदान हेतु शासकीय भूमि आरक्षित करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं।

23. बहुत से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि राज्य के लोगों को छत्तीसगढ़ में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके बाद भी अन्यत्र जाने की आवश्यकता पड़ने पर, मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए एक विस्तृत अधिनियम का प्रारूप तैयार कर, उसमें सुधार हेतु सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करके उसे अंतिम रूप दिया गया है। राज्य में श्रमिकों के कल्याण की अनेक योजनाओं को प्राथमिकता से हाथ में लिया गया है। डोंगरगढ़ तथा बिलासपुर में कार्यरत् बीड़ी श्रमिकों के लिए 1500 आवासों तथा मंडियों में कार्यरत हमालों के लिए धमतरी में 250 आवास बनाने की योजना स्वीकृत हुई है। रायपुर जिले में बाल श्रमिक परियोजना स्वीकृत है। राज्य में कर्मचारी बीमा सेवाओं के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं में गुणात्मक सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत भिलाई, चांपा, कोरबा में नए औषधालय खोले जा रहे हैं।

24. मेरी सरकार लोकहित में अधिकारों तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण की हिमायती है परंतु सत्ता के दुरूपयोग को रोकने के प्रति गंभीर है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध अर्धन्यायिक कार्यवाही के लिये सक्षम ट्रिब्यूनलों का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे विकेन्द्रीकरण का उपयोग आम जनता की बेहतरी के लिए हो। पंचायती राज व्यवस्था में और अधिक सुधारों के लिए एक समीक्षा समिति का गठन भी किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव की समस्याओं के निष्पक्ष निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सार्थक बनाने हेतु महिला पंच–सरपंचों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें गैर शासकीय संस्थाओं की भी भागीदारी

होगी। छत्तीसगढ़ में 'राज्य ग्रामीण विकास संस्थान' का शिलान्यास किया जा चुका है। इस केन्द्रीय संस्थान के निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा भूमि प्रदान करने औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं तथा भवन का निर्माण केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध राशि से कराया जाएगा। इस संस्थान के स्थापित होने से पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। साथ ही इस संस्थान द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित अनुसंधान कार्य भी किया जाएगा।

25. गांवों में मकानों में सुधार से ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है, इसलिए मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि धारकों द्वारा धारित भूमि का नक्शा बनाने, प्लाट नम्बर देने और उसकी भू–अधिकार पुस्तिका में दर्ज करने का आदेश 22 फरवरी, 2001 को जारी कर दिया गया है और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

26. राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए एक स्वस्थ एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाया जा रहा है। राज्य की विकासोन्मुखी औद्योगिक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लोगों की भागीदारी तय करते हुए, अशासकीय सदस्यों की एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति गठित की गई है, जो संतुलित औद्योगिक विकास नीति का प्रारूप तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस प्रेरक वातावरण के परिणामस्वरूप कुछ प्रमुख औद्योगिक समूहों ने राज्य में निवेश हेतु रूचि दिखाई है। राज्य में विदेशी निवेशकों को आकृष्ट करने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य शासन के विभिन्न मंत्रालयों एवं भारत सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु एक 'नीतिगत प्रबंधन दल' का गठन किया गया है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 'छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रोमोशन सोसायटी' (चिप्स) का गठन किया जा चुका है।

27. मेरी सरकार आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में निजी पूंजी निवेश और आर्थिक विकास में निजी क्षेत्रों की भूमिका को महत्व देती है। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम ईमानदार प्रयासों के बावजूद लाभप्रद न बन सकें, तो ऐसी सार्वजनिक सम्पत्ति के निष्पक्ष मूल्यांकन उपरान्त निजीकरण की भी मेरी सरकार हिमायती है परंतु वित्तीय रूप से सेहतमंद सार्वजनिक उपक्रमों के औचित्यहीन कारणों और अपारदर्शी प्रक्रिया से होने वाले निजीकरण का विरोध किया जाएगा। साथ ही अवांछनीय निजीकरण के मामलों में सार्वजनिक उपक्रमों की हैसियत से प्रदत्त विभिन्न रियायतों की भी समीक्षा होगी। राज्य में हाथकरघा उद्योग के संवर्धन एवं विकास हेतु, टसर कोसा पर लगने वाले 2 प्रतिशत वाणिज्यिक कर एवं कोसाफल पर लगने वाले 8 प्रतिशत वाणिज्य कर को मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन की समुचित एवं स्थायी व्यवस्था के लिए रायपुर में 'छत्तीसगढ़ हाट' की स्थापना हेतु पहल की जा रही है। राज्य में शासकीय विभागों एवं उपक्रमों की जरूरतों के लिए

अब सीधे बुनकर समितियों द्वारा हाथकरघा पर निर्मित वस्त्र ही प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है। इससे क्षेत्र के हाथकरघा बुनकरों के रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बस्तर संभाग में हस्तशिल्प के विकास हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति हस्तशिल्प के संरक्षण एवं संवर्धन, हस्तशिल्प के गुणात्मक सुधार और उन्हें राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की संभावनाओं पर अपने सुझाव देगी। छत्तीसगढ़ रेशम परियोजना के अन्तर्गत लगभग 4 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में टसर पौधरोपण किया जा रहा है जिससे क्षेत्र के लोगों में रेशम की गतिविधियों के प्रति लगाव बढ़ा है।

28. मेरी सरकार ने राज्य में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता तथा इसके निरन्तर प्रदाय के लिए ठोस उपाय करने का संकल्प लिया था। हर्ष का विषय है कि उपभोक्ताओं को नए वर्ष के उपहार स्वरूप एक जनवरी से प्रदेश के ऐसे सभी क्षेत्रों में जहां तकनीकी रूप से संभव है, बिजली कटौती पूरी तरह बंद कर दी गई। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के विद्युत गृहों की स्थापित क्षमता, केन्द्रीय क्षेत्र से प्राप्त हिस्सा और केप्टिव संयंत्रों की उत्पादन क्षमता मिलाकर, स्थिति भले ही संतोषजनक हो, परंतु आने वाले समय में बिजली की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए मेरी सरकार राज्य में उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने की दिशा में कारगर पहल करेगी, जिसमें निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सरकार के संकल्प के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा विद्युत उत्पादन एवं वितरण के लिए भार प्रेषण केन्द्र (लोड डिस्पेच सेन्टर) शक्तिनगर, खेदामारा में प्रारंभ किया जा चुका है। दूरस्थ क्षेत्रों में भी 33 के.वी. पारेषण प्रणाली का शेष कार्य चरणबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण किया जाएगा ताकि पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति में व्यवधान से संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सके। वर्तमान संसाधनों के कुशल उपयोग से कार्य दक्षता तथा कार्य निष्पत्ति में सुधार के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। कम वोल्टेज की समस्या के निदान हेतु नए उपकेन्द्र कांकेर, सरायपाली, सारंगढ़, कवर्धा, मोपका (बिलासपुर), कचना (रायपुर) में वर्ष 2001–2002 के दौरान स्थापित किए जाने की योजना है। राज्य के कुल 19,720 आबाद ग्रामों में से 18,075 ग्राम विद्युतीकृत हैं। शेष 1,645 ग्रामों में से 1,474 वन ग्रामों को छोड़कर बाकी बचे 171 गांवों को शीघ्र विद्युतीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। ढाई माह के अल्प समय में 189 मजरा टोलों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जिन कास्तकारों द्वारा विद्युत पम्प कनेक्शन हेतु औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई थीं, उनके पंप कनेक्शन हेतु लाइन बिछाने के कार्य में भी, राज्य गठन के बाद गति आई है।

29. राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की असीम संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थिति इन ऊर्जा स्रोतों पर आधारित तकनीक के उपयोग के अनुकूल है। सघन वनों से घिरे हुए सुदूर आदिवासी अंचल में बिजली पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने सौर ऊर्जा के विकल्प को उत्तम मानकर सार्थक पहल की है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार के उपक्रम सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के माध्यम से बस्तर संभाग के उसूर तथा भोपालपट्नम विकासखंड के ग्रामों को सौर ऊर्जा से प्रकाशित करने के लिए 11 करोड़ रूपए की परियोजना पर कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना से ऐसे 90 ग्रामों

में प्रत्येक घर को रोशन किया जा सकेगा जहां सघन वनों के कारण बिजली पहुंचाना संभव नहीं है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा अपने विशेषज्ञों एवं स्थानीय ग्रामीणों को पर्याप्त प्रशिक्षण देकर अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक ग्राम में इन सौर ऊर्जा संयंत्रों का रख–रखाव भी सुनिश्चित किया जाएगा।

30. यह सभी के लिए हर्ष का विषय है कि रायगढ़ जिले की ईव नदी के कछार में हीरा कणों की पुष्टि हो चुकी है। रायपुर जिले के मैनपुर क्षेत्र में 4 किम्बरलाइट पाइप तथा बस्तर जिले के टोकापाल क्षेत्र में 2 किम्बरलाइट पाइप की खोज की गयी है। इन किम्बरलाइट पाइप में से बेरहाडीह एवं पायलीखंड क्षेत्र में हीरा कणों की पुष्टि की जा चुकी है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में स्वर्ण तथा टिन प्राप्ति के संकेत प्राप्त हुए हैं। बस्तर जिले में रत्न/उपरत्न श्रेणी का कोरंडम पाया गया है। छत्तीसगढ़ में खनिजों के यथोचित खनन तथा राज्य के विकास में उपयोग हेतु नयी खनिज नीति को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोयले की रायल्टी बढ़ाने के लिए सभी कोयला उत्पादक राज्यों से विचार–विमर्श किया जाएगा।

31. राज्य में प्रचलित कराधान व्यवस्था को मेरी सरकार व्यापक जनहित में सरल एवं युक्तियुक्त बनाना चाहती है। कराधान व्यवस्था में सुधार के लिए गठित समिति का प्रथम अंतरिम प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हो चुका है जिस पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा। आबकारी नीति 2001–2002 के तहत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल 2001 से नीलाम कराया जा रहा है। शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि आबकारी नीति में इस परिवर्तन से आदिवासी परिवारों को परेशानी न हो, अतः अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी आबकारी अधिकारी/पुलिस अधिकारी द्वारा जिलाधीश अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की पूर्व अनुमति के बिना, किसी आदिवासी परिवार के विरूद्ध आबकारी अपराध से संबंधित किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के संसाधनों के समुचित एवं प्रभावी उपयोग के लिए योजनाएं बनाने हेतु राज्य योजना मंडल गठित है। राज्य के प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति गठित है राज्य के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 2001–2002 के लिये 1106.74 करोड़ रू. की राशि प्रस्तावित की गई है। तद्नुसार वार्षिक योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

32. छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने एवं किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुस्तरीय प्रयास जारी हैं। फसल चक्र में सार्थक परिवर्तन कर किसानों को अलाभकारी फसलों के बदले लाभकारी फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, वहां धान की फसल के एवज में दलहन और तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के संबंध में कार्य–योजना बनायी गई है, जिसके अन्तर्गत आगामी खरीफ मौसम में 95,000 हेक्टेयर का अधिक रकबा दलहन–तिलहन फसलों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। पहली बार छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम को एक आंदोलन का रूप दिया गया है, जिसके अन्तर्गत किसानों की आर्थिक स्थिति में

व्यापक सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 25,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उद्यानिकी विकास हेतु उपयुक्त है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के लिये वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। बस्तर क्षेत्र में उद्यानिकी विकास की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 'एकीकृत उद्यानिकी विकास परियोजना' प्रस्तावित की जा रही है। कृषि उपज मण्डियों के विकास के लिए 'मेक्रो मेनेजमेन्ट कार्ययोजना' को लागू किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उत्पादित वस्तुओं का मण्डियों के माध्यम से उचित मूल्य प्राप्त हो सके। राज्य में किसानों का मनोबल ऊंचा रखने तथा कृषि की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा माटीपुत्र डॉ. खूबचंद बघेल की स्मृति में 2 लाख रू. के 'कृषक–रत्न' पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो प्रतिवर्ष प्रदेश के उन्नतिशील और उत्कृष्ट किसान को प्रदान किया जाएगा।

33. मेरी सरकार 'अमूल' पद्धति के आधार पर सहकारी डेयरी विकास की गतिविधियों का विस्तार प्रदेश के 'ऑपरेशन फ्लड' के माध्यम से अछूते इलाकों में करने के लिए प्रयासरत है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आय का अत्यन्त महत्वपूर्ण जरिया बनेगी। उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि के लिए, घर पहुंच कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध कराने तथा धान–पैरा को पौष्टिक संतुलित पशु आहार में परिवर्तित करने हेतु लगभग 29 करोड़ रू. की कार्य–योजनाएं तैयार कर केन्द्र को भेजी गई हैं। मत्स्य विकास कार्यक्रम से प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है, जिससे प्रतिवर्ष 15 हजार लोगों को काम मिलेगा। मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब तक 35 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया जा चुका है।

34. किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिले, इस उद्देश्य से राज्य में समर्थन मूल्य के अंतर्गत अब तक लगभग 4.92 लाख मी. टन धान की खरीदी की जा चुकी है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 16,27,626 नीले रंग के राशन कार्ड वितरित कर इन कार्डधारियों को अधिकतम 20 किलो खाद्यान्न प्रति कार्ड, रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 'छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड' के गठन का निर्णय लिया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खासकर पहुंचहीन क्षेत्रों में 83 चलित वाहनों के माध्यम से साप्ताहिक हाट–बाजारों में बिना राशन कार्ड के रियायती दरों पर खाद्यान्न का वितरण कराया जाना लाभप्रद है। वर्षा ऋतु के पूर्व राज्य के पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न का समुचित भंडारण तथा वितरण समय पूर्व कर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

35. मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशील तथा उत्तरदायी व्यवस्था को प्रभावशील बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित नीति विषयक अनुशंसा के लिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत

'आदिम जाति मंत्रणा परिषद' का गठन किया जा चुका है। अनुसूचित जाति वर्ग के स्वरोजगार तथा आर्थिक कल्याण कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु वित्त विकास निगम गठित किया जा चुका है। रायपुर जिले के दूरस्थ गरियाबंद क्षेत्र में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति 'कमार' के विकास के लिए 3.87 करोड़ रूपए की योजना स्वीकृति हेतु केन्द्र को भेजी गई है। बस्तर संभाग के अंतर्गत अबूझमाड़ के निवासियों के विकास हेतु नये सिरे से कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे।

36. अपने संकल्प के अनुसार मेरी सरकार ने 'ई गवर्नेन्स' की दिशा में पहले चरण में रायपुर नगर निगम में 'स्मार्ट सिटी' पायलेट परियोजना 26 जनवरी, 2001 को प्रारंभ की है। स्मार्ट सिटी परियोजना को रायपुर में पूरी तरह लागू करने के बाद इसे अन्य स्थानीय निकायों में भी प्रारंभ किया जाएगा। मेरी सरकार इलेक्ट्रानिक शासन प्रणाली स्थापित कर गति, पारदर्शिता व भ्रष्टाचार रोकने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके लिए राज्य मंत्रालय में आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं से युक्त लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित करने का कार्य 'एन.आई.सी.' व 'एन.आई.सी. सर्विसेस इनकॉर्पोरेटेड' के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। साथ ही एन.आई.सी. ने राज्य के बचे हुए शेष 6 जिलों में भी एन.आई.सी. जिला केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कोषालय हमारी वित्त व्यवस्था का प्रमुख अंग है। कोषालय प्रशासन के उन्नयन के लिये ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से राज्य के कोषालयों एवं उप–कोषालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कम्प्यूटरों के प्रदाय के साथ–साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। इस सूचना तकनीक के क्रियान्वित होने पर प्रदेश के 17 कोषालय एवं 46 उपकोषालय आपस में एवं शासन से सीधे जुड़ जाएंगे और शासन को आय–व्यय के अद्यतन आंकड़े तथा आवश्यक सूचनाएं समय पर प्राप्त हो सकेंगी। जिला योजना समितियों को कार्यपालिक अधिकार देकर जिला सरकार की अवधारणा दी गई थी, जिसके परिणामों के मूल्यांकन और समीक्षा हेतु एक समिति भी गठित की गई है। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 'जिला योजना समिति अधिनियम' में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

37. मेरी सरकार ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता के लिए आंतरिक स्रोतों के अलावा बाह्य स्रोतों की भी मदद ली जाए। संस्थागत पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 'संस्थागत वित्त संचालनालय' का भी गठन कर दिया गया है। विकास कार्यक्रमों से संलग्न बैकिंग प्रणाली के बीच समन्वय के लिए भारतीय स्टेट बैंक को राज्य का लीड बैंक बनाया गया है।

38. छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों, सिंचाई, बिजली, संचार आदि मूलभूत सुविधाओं के स्तर का उन्नयन करने के लिए मेरी सरकार ने 'छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम' के गठन की कार्यवाही पूर्ण कर ली है। निगम के अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे। इससे अधोसंरचना के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा सकेगा तथा देश–विदेश से निजी पूंजी निवेश भी अधोसंरचना हेतु प्राप्त किया जा सकेगा।

39. मेरी सरकार ने राज्य में पुलिस को 'परित्राणाय साधूनाम्' का कर्मसूत्र दिया है। पुलिस का मनोबल तथा जनसेवा हेतु उनकी दक्षता बढ़ाने पुलिस बल के अत्याधुनिकीकरण के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई थी। जिसके तहत भारत शासन से वर्ष 2000–2001 के लिए 3.8 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिल चुकी है। इतनी ही राशि राज्य शासन द्वारा मैचिंग ग्रान्ट के रूप मे दी गई है। पुलिस बल के अत्याधुनिकीकरण के लिए अगले पांच वर्ष में भारत शासन प्रतिवर्ष 19 करोड़ रूपए की राशि प्रदाय करेगा। 11वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत 984 लाख रूपए का अनुदान प्रस्ताव भेजा गया है। होमगार्ड, सैनिकों के मान वेतन एवं भोजन राशि में वृद्धि की गई है। पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कार घोषित किए गए हैं। राज्य के 6 जिलों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, पेयजल, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा आदि से संबंधित विकास गतिविधियों हेतु 572 करोड़ रू. के प्रस्ताव तैयार कर केन्द्रीय मदद हेतु भेजे गए हैं। जहां मेरी सरकार इस समस्या के सामाजिक–आर्थिक पहलुओं की ओर ध्यान दे रही है, वहीं आवश्यकतानुरूप कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दो सशस्त्र बल की बटालियनों की स्वीकृति दी गई है और इसके गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। भारत शासन द्वारा भी एक इंडियन रिजर्व बटालियन की स्वीकृति दी गई है।

40. मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जेलों को सुधार तथा संस्कार गृहों के रूप में कार्य करने की नीति बनाई है जो बंदियों के पुनर्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। शासन ने 18 दिसम्बर गुरू घासीदास जयंती एवं 26 जनवरी, 2001 गणतंत्र दिवस पर, राज्य की जेलों से 218 आजीवन कारावास से दण्डित कैदियों को रिहा किया और 800 बंदी माफी से लाभान्वित हुए। छत्तीसगढ़ की जेलों में बंदियों के पुनर्वास हेतु विभिन्न उद्योगों के लिए पूर्व की तुलना में अधिक राशि इस वर्ष उपलब्ध कराई गई है तथा मोटर वर्कशाप, लांड्री वर्क, ऑफसेट प्रिंटिग जैसी गतिविधियों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। अंबिकापुर में जिला जेल का उन्नयन किया गया है।

41. छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पृथक राज्य परिवहन प्राधिकार का गठन किया गया है। राज्य की विकास नीतियों को मूर्तरूप देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने हेतु छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर चार परिवहन चेक पोस्टों की स्थापना की गई है तथा प्रदेश के चारों ओर की सीमाओं पर संयुक्त चेक पोस्ट स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। इस विभाग द्वारा प्रदूषण जांच केन्द्रों की स्थापना की पहल की जा रही है।

42. माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ में सर्वांगीण विकास की अपार संभावनाओं को यथार्थ में ढालने की जो शुरूआत मेरी सरकार ने की है, इससे जनाकांक्षाओं में भी सापेक्षिक विस्तार हुआ है। सरकार को इस बात का बखूबी अहसास है कि जितना काम किया गया है, उससे बहुत अधिक करना शेष है। फिर भी छत्तीसगढ़ के प्रचुर प्राकृतिक और मानव संसाधनों के उचित उपयोग तथा उचित योजनाओं पर अमल के

माध्यम से 'सबसे अमीर धरती–सबसे गरीब लोग' का विरोधाभास करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इन प्रयासों से राज्य में मानव विकास के आंकड़े नवीन ऊंचाईयों को स्पर्श करेंगे। गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं, नागरिक जीवन के उन्नयन का मजबूत आधार बनेंगी। मुझे विश्वास है कि व्यापक जनभागीदारी से विकास और 'सादगी के साथ जनसेवा' का संकल्प लेने वाली मेरी सरकार, राज्य में विकास का एक आदर्श वातावरण बनाने में सफल होगी। मैं कामना करता हूं कि आने वाले महीनों की कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों में भी राज्य की जनता का पूरा सहयोग इस संकल्प को पूरा करने में मिलेगा।

।। जय–हिन्द ।।